

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 11 अगस्त, 2015

विषय-जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत द्वालीसेरा (पीपली-दयोडा) के पास भारत-नेपाल सीमा पर काली नदी के ऊपर 122 मी. विस्तार स्टील डैक सस्पेंशन बैली ब्रिज के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत द्वालीसेरा (पीपली) के पास भारत-नेपाल सीमा पर काली नदी पर झूलापुल निर्माण की स्वीकृति शासनादेश संख्या-455/111-2/06-97(प्रा0आ0)/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2006 द्वारा लम्बाई 120 मी. झूलासेतु जिसकी लागत धनराशि ₹ 215.10 लाख है, हेतु प्रदान की गई है।

उक्त झूलासेतु के निर्माण के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न हो पाने के कारण सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। वर्ष 2006 से वर्तमान तक निर्माण सामग्री एवं श्रमिक की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2006 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 215.10 लाख से स्वीकृत लम्बाई 120 मी. के झूलासेतु का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी सम्पूर्ण लागत ₹ 688.32 लाख (₹ 215.10 लाख पूर्व स्वीकृत लागत+₹ 473.22 लाख पुनरीक्षित लागत) है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 524.84 लाख (₹ 215.10 लाख पूर्व स्वीकृत लागत+₹ 309.74 लाख पुनरीक्षित लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय किये जाने की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2- उक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-455/111-2/06-97(प्रा0आ0)/2005 दिनांक 24 फरवरी, 2006 द्वारा लम्बाई 120 मी. झूलासेतु के लिए स्वीकृत लागत धनराशि ₹ 215.10 लाख को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण लागत धनराशि ₹ 524.84 लाख लाख से घटाते हुए, पुनरीक्षित लागत धनराशि ₹ 309.74 लाख (₹ तीन करोड़ नौ लाख चौहत्तर हजार मात्र) में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पश्चात् व्यय कर दी



गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। यह शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3- उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण लागत धनराशि ₹ 524.84 लाख के सापेक्ष ₹ 375.89 लाख के लागत के कार्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5- कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

6- स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

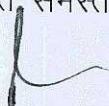
7- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

10- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

11- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।





12- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22 लेखाधीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800 अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा विभिन्न पत्रावलियों में दिये गये परामर्शानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)

अपर सचिव

संख्या:- 55/6/111(2)/15-97(प्रा०आ०)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, ~~पिथौरागढ़~~।
4. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, ~~पिथौरागढ़~~।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/~~पिथौरागढ़~~ उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा/से,

(ए.एस. पागती)

उप सचिव